



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1948 (श0)

(सं० पटना 1060) पटना, सोमवार, 31 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त 2026

एस० ओ० 203 दिनांक 31 अगस्त 2026—जबकि, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 34 की उपधारा (3) के खंड (प) द्वारा समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा एक निरीक्षण स्कीम निर्धारित करने के लिए सशक्त किया गया है, जो वेब-आधारित निरीक्षण के सृजन तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना मंगाए जाने का प्रावधान कर सकती है;

और जबकि, उक्त संहिता की धारा 34 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि ऐसी निरीक्षण स्कीम तैयार की जा सकती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे मापदंडों के आधार पर विशेष निरीक्षण के प्रावधान तथा रोजगार की विशेषताओं, कार्य की प्रकृति और कार्यस्थलों की विशेषताओं को ध्यान में रखा जा सकता है;

और जबकि, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 32 के उपनियम (2) में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सभी स्थापनाओं के निरीक्षण को अनिवार्य करने तथा स्थापना के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर एक वेब-आधारित निरीक्षण स्कीम निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है।

और जबकि, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वर्ष 2026 के लिए बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के अंतर्गत जोखिम-आधारित निरीक्षण के उद्देश्य से स्थापनाओं को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करने की सलाह दी है;

अतः अब, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 34 की उपधारा (3) के खंड (i) को उपधारा (4) के खंड (ग) और (घ) तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 32 के उपनियम (2) के साथ पठित करने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, बिहार के राज्यपाल, स्थापनाओं को निम्न जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित योजना को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।-

- (1) इस स्कीम को बिहार स्थापनाओं का जोखिम आधारित वर्गीकरण (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ) योजना, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) यह बिहार राज्य में स्थित प्रत्येक ऐसी स्थापना पर लागू होगी, जिस पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 लागू होती है और जिसके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है।
- (3) इस स्कीम में निहित कोई बात संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी स्थापना, या किसी खान, या ऐसी किसी स्थापना पर लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में केंद्र सरकार समुचित सरकार है।
- (4) यह स्कीम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. "परिभाषाएँ"।-

- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "संहिता" से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) अभिप्रेत है;
 - (ख) "बिहार नियम" से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियम, 2026 अभिप्रेत है;
 - (ग) "कैलेंडर वर्ष" से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि अभिप्रेत है;
 - (घ) "बड़ी दुर्घटना जोखिम स्थापना" या "MAH स्थापना" से ऐसी स्थापना अभिप्रेत है, जिसमें बिहार नियमों की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट कोई खतरनाक पदार्थ, जो उक्त नियमों के "नियम 2(7)" के अधीन बनाए गए हैं और संहिता की "धारा 2" की उपधारा (1) के खंड (zb) से संबंधित हैं, उस अनुसूची में उसके सामने विनिर्दिष्ट सीमा मात्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा में विनिर्मित, प्रसंस्कृत, संचालित या भंडारित किया जाता है;
 - (ङ) "खतरनाक प्रक्रिया" का वही अर्थ होगा जो संहिता की "धारा 2" की उपधारा (1) के खंड (za) में, उसके साथ संलग्न "प्रथम अनुसूची" के साथ पठित, दिया गया है;
 - (च) "पोर्टल" से बिहार नियमों के "नियम 32" के उपनियम (2) के अधीन विभाग द्वारा अनुरक्षित वेब-आधारित निरीक्षण पोर्टल अभिप्रेत है;
 - (छ) "जोखिम स्कोर" से इस स्कीम के "Annexure-A" के अनुसार परिकलित स्कोर अभिप्रेत है;
 - (ज) "नियमित निरीक्षण" से निरीक्षण स्कीम के अधीन सामान्य क्रम में किया गया निरीक्षण अभिप्रेत है, और इसमें पैराग्राफ 15 में निर्दिष्ट निरीक्षण सम्मिलित नहीं होगा;
 - (झ) "श्रमिक" का वही अर्थ होगा जो संहिता की "धारा 2" की उपधारा (1) के खंड (zzl) में दिया गया है, और इस स्कीम के अधीन प्रत्येक सीमा के प्रयोजन के लिए इसमें खंड (m) के अर्थ में संविदा श्रम तथा स्थापना में नियोजित अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक भी सम्मिलित होंगे।
- (2) इस स्कीम में प्रयुक्त ऐसे शब्द और पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु संहिता या बिहार नियमावली में परिभाषित किए गए हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो संहिता या उन नियमों में उन्हें दिए गए हैं।

3. स्थापनाओं का वर्गीकरण"।-

- (1) प्रत्येक स्थापना को तीन श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और निम्न जोखिम।
- (2) वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा-
 - (क) पैराग्राफ 4, 6 और 8 में विनिर्दिष्ट गुणात्मक मानदंड; और
 - (ख) Annexure-A के अधीन परिकलित जोखिम स्कोर।

(3) जहाँ पैराग्राफ 4, 6 और 8 में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर निर्धारित श्रेणी, **Annexure-A** के अधीन जोखिम स्कोर के आधार पर निर्धारित श्रेणी से भिन्न हो, वहाँ स्थापना को **दोनों श्रेणियों में से उच्चतर श्रेणी** में रखा जाएगा।

(4) पैराग्राफ 5, उप-पैराग्राफ (3) में अंतर्विष्ट किसी बात या **Annexure-A** में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

4. **उच्च जोखिम वाली स्थापनाएँ।**—किसी स्थापना को उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक शर्तें उस पर लागू होती हैं:—

- (क) स्थापना में ऐसी दुर्घटना हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो, या ऐसी शारीरिक क्षति हुई हो, जिसका विवरण संहिता की **“धारा 10”** के अधीन अधिसूचित किया गया है, और ऐसी दुर्घटना की सूचना पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान दी गई है या दी जानी अपेक्षित थी;
- (ख) पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसी खतरनाक घटना हुई है, जिसकी सूचना संहिता की **धारा 11** के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, या संहिता की **तृतीय अनुसूची** में विनिर्दिष्ट ऐसी बीमारी हुई है, जिसकी सूचना उक्त संहिता की **धारा 12** के अधीन दिया जाना अपेक्षित है;
- (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही संस्थित की गई है, जो संहिता की **धारा 114** की उपधारा (1) के अधीन, या मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन शमनीय नहीं है, या किसी बालक के नियोजन के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है;
- (घ) स्थापना एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें सामान्यतः **“पाँच सौ या अधिक श्रमिक”** नियोजित हैं, या ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कोई खतरनाक प्रक्रिया संचालित की जाती है, या ऐसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य की स्थापना है जिसमें सामान्यतः **“दो सौ पचास या अधिक श्रमिक”** नियोजित हैं, जो संहिता की **धारा 22** की उपधारा (2) में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट सीमा है;
- (ङ) स्थापना में नियोजित **“पचास प्रतिशत से अधिक श्रमिक संविदा श्रमिक या अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक”** हैं, या संहिता की **“धारा 57”** द्वारा अनुमत के अतिरिक्त स्थापना की किसी मूल गतिविधि (core activity) में संविदा श्रमिक नियोजित किए जाते हैं;
- (च) बिहार नियमों के **नियम 34** के अधीन **प्ररूप—XII** में जारी कोई निषेध या सुधार सूचना लंबित है और उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसका अनुपालन नहीं किया गया है;
- (छ) **Annexure-A** के अधीन परिकलित जोखिम स्कोर 4.5 या उससे अधिक है; या
- (ज) स्थापना पैराग्राफ 5 के अंतर्गत आती है।

5. **अनिवार्य रूप से उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली स्थापनाएँ।**—**Annexure-A** के अधीन परिकलित जोखिम स्कोर में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी स्थापना को प्रत्येक मामले में **उच्च जोखिम** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वह मध्यम जोखिम या निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी, यदि वह—

- (क) बड़ी दुर्घटना जोखिम स्थापना (MAH Installation) है;
- (ख) संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (za) में परिभाषित, उक्त धारा के साथ पठित **प्रथम अनुसूची** के अर्थ में, कोई **“खतरनाक प्रक्रिया”** संचालित करती है; या
- (ग) बिहार नियमों की **अनुसूची—II** में विनिर्दिष्ट किसी खतरनाक पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, संचालन या भंडारण उसमें विनिर्दिष्ट सीमा मात्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा में करती है।

6. **मध्यम जोखिम वाली स्थापनाएँ।**—

- (1) ऐसी स्थापना, जिसे पैराग्राफ 4 या पैराग्राफ 5 के अधीन उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और जो पैराग्राफ 8 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा नहीं करती है, उसे **मध्यम जोखिम** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (2) उप-पैराग्राफ (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी स्थापना को **“मध्यम जोखिम”** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जहाँ पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान उसके विरुद्ध संस्थित एकमात्र कार्यवाही ऐसे अपराध से संबंधित है, जो संहिता की **धारा 114** की उपधारा (1) के अधीन

शमनीय है, या ऐसा अपराध है जिसके लिए विभाग द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जांच के पश्चात अधिरोपणीय दंड का प्रावधान है।

- (3) ऐसी स्थापना, जिसका **Annexure-A** के अधीन परिकलित जोखिम स्कोर 2.5 या उससे अधिक, किंतु 4.5 से कम है, उसे पैराग्राफ 4 और 5 के अधीन रहते हुए मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

7. मध्यम जोखिम वाली स्थापनाओं के लिए तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा और प्रमाणन"।—

- (1) मध्यम जोखिम वाली स्थापनाओं को संहिता की धारा 37 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए स्थापनाओं के "एक वर्ग" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।
- (2) राज्य सरकार, संहिता की धारा 37 की उपधारा (1) को बिहार नियमों के नियम 35 के साथ पठित करते हुए, एक पृथक अधिसूचना द्वारा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी तथा ऐसे विशेषज्ञों की विशिष्ट योग्यता और अनुभव, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अधिसूचित करेगी।
- (3) उप-पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने तक उप-पैराग्राफ (4) से (7) में अंतर्विष्ट कोई बात प्रभावी नहीं होगी।
- (4) किसी मध्यम जोखिम वाली स्थापना की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा और प्रमाणन का कार्य विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक (randomised) तरीके से पैनल में शामिल किसी विशेषज्ञ को सौंपा जाएगा, जो संहिता की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार होगा; और कोई भी स्थापना स्वयं उस विशेषज्ञ का चयन, नियुक्ति या नियोजन नहीं करेगी जो उसका लेखापरीक्षण करता है।
- (5) पैनल में शामिल विशेषज्ञ स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति से "लेखापरीक्षा और प्रमाणन दोनों" करेगा तथा संहिता की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अनुसार, रिपोर्ट नियोक्ता और क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को प्रस्तुत करेगा।
- (6) जहाँ किसी मध्यम जोखिम वाली स्थापना का इस प्रकार लेखापरीक्षण और प्रमाणन किया गया है तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट स्कीम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत कर दी गई है, वहाँ वह स्थापना स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियमित निरीक्षण से छूट प्राप्त करेगी।
- (7) उप-पैराग्राफ (6) के अधीन छूट उपलब्ध नहीं होगी और स्थापना को नियमित निरीक्षण के लिए लिया जाएगा, जहाँ स्थापना—
- (क) उसे सौंपे गए लेखापरीक्षण के लिए स्वयं को उपलब्ध कराने में विफल रहती है, या विनिर्दिष्ट समय के भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहती है; या
- (ख) बिहार नियमों के नियम 29 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रारूप-IX में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहती है।

8. निम्न जोखिम वाली स्थापनाएँ।—किसी स्थापना को निम्न जोखिम के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा, जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हों :-

- (क) वह ऐसी स्थापना नहीं है जो पैराग्राफ 4 या पैराग्राफ 5 के अंतर्गत आती है;
- (ख) पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों के दौरान स्थापना में ऐसी कोई दुर्घटना, खतरनाक घटना या अधिसूचनीय बीमारी नहीं हुई है, जिसकी सूचना संहिता की धारा 10, धारा 11 या धारा 12 के अधीन दिया जाना अपेक्षित है;
- (ग) पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों के दौरान स्थापना के विरुद्ध किसी भी श्रम संहिता के अधीन कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है;
- (घ) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में से प्रत्येक के लिए प्रारूप-IX में वार्षिक विवरणी" बिहार नियमों के नियम 29 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विधिवत प्रस्तुत की गई है; और
- (ङ.) **Annexure-A** के अधीन परिकलित जोखिम स्कोर 2.5 से कम है।

9. निम्न जोखिम वाली स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणन।—

- (1) निम्न जोखिम वाली स्थापना, संहिता और बिहार नियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले अनुपालनों के संबंध में स्व-प्रमाणन की सुविधा की हकदार होगी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-
- (क) स्थापना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्व-प्रमाणन स्कीम में सम्मिलित है;

- (ख) स्थापना बिहार नियमों के नियम 29 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पोर्टल पर प्रारूप-IX में अपनी वार्षिक विवरणी अपलोड करती है और विहित रजिस्ट्रारों तथा अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित करती है; और
- (ग) स्थापना प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में स्व-प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करती है।
- (2) ऐसी स्थापना, जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक विवरणी अपलोड करने में विफल रहती है, स्व-प्रमाणन के लाभ या पैराग्राफ 10 के अधीन कम निरीक्षण आवृत्ति की हकदार नहीं होगी और उस वर्ष के लिए उसे मध्यम जोखिम वाली स्थापना माना जाएगा।
- (3) विभाग प्रत्येक वर्ष स्व-प्रमाणित निम्न जोखिम वाली स्थापनाओं में से कम-से-कम पाँच प्रतिशत स्थापनाओं का, पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से चयन करके, निरीक्षण द्वारा सत्यापन कराएगा।
- (4) जहाँ स्व-प्रमाण-पत्र किसी महत्वपूर्ण विशिष्टता के संबंध में मिथ्या पाया जाता है, वहाँ स्थापना को ऐसी मिथ्या पाए जाने की तारीख से उच्च जोखिम के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा, स्व-प्रमाणन की सुविधा तीन वर्षों के लिए वापस ले ली जाएगी और संहिता के सुसंगत दंडात्मक उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

10. नियमित निरीक्षण की आवृत्ति।—

- (1) नियमित निरीक्षण, संहिता की धारा 34 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अनुसार, प्रतिष्ठान और निरीक्षक-सह-सुकारक के यादृच्छिक (randomised) चयन द्वारा पोर्टल के माध्यम से नियत किए जाएंगे।
- (2) पैराग्राफ 15 के अधीन रहते हुए, नियमित निरीक्षण की आवृत्ति सामान्यतः निम्नानुसार होगी—
 - (क) उच्च जोखिम — प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम एक बार;
 - (ख) मध्यम जोखिम — प्रत्येक तीन कैलेंडर वर्षों में कम-से-कम एक बार, अथवा जहाँ प्रतिष्ठान का पैराग्राफ 7 के उपपैराग्राफ (6) के अंतर्गत अंकेक्षण और प्रमाणन किया जा चुका है, वहाँ उस उपपैराग्राफ में उपबंधित रीति से; और
 - (ग) निम्न जोखिम — प्रत्येक पाँच कैलेंडर वर्षों में कम-से-कम एक बार।
- (3) उपपैराग्राफ (2) के खंड (ग) को तथा बिहार नियमों के नियम 32 की उपनियम (2) में निहित इस अपेक्षा को कि सभी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण अनिवार्य किया जाए, प्रभावी करने के लिए, पोर्टल प्रत्येक वर्ष निम्न जोखिम प्रतिष्ठानों में से लगभग एक-पाँचवाँ भाग निरीक्षण हेतु चयनित करेगा, ताकि प्रत्येक निम्न जोखिम प्रतिष्ठान का निरीक्षण प्रत्येक पाँच कैलेंडर वर्षों में कम-से-कम एक बार हो सके; और किसी वर्ष में इस प्रकार चयनित संख्या, निम्न जोखिम प्रतिष्ठानों की कुल संख्या के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

11. वर्गीकरण की संगणना, संसूचन और वैधता।—

- (1) जोखिम स्कोर और उससे परिणामी वर्गीकरण की संगणना पोर्टल पर—
 - (क) संहिता की धारा 3 के अधीन प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के समय, अथवा किसी कारखाने की दशा में, बिहार नियमों के नियम 64 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के समय; और
 - (ख) प्रत्येक वर्ष, प्रपत्र-IX में वार्षिक विवरणी दाखिल किए जाने पर, पुनः की जाएगी।
- (2) यह वर्गीकरण, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, अनुज्ञप्ति, वार्षिक विवरणी, संहिता की धारा 33 के अधीन रखे गए रजिस्ट्रारों, बिहार नियमों के नियम 30 के अधीन प्रपत्र-X में दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के रजिस्टर, तथा उपपैराग्राफ (3) के अधीन प्रस्तुत स्व-घोषणा में उपलब्ध विवरणों से संगणित की जाएगी।
- (3) प्रत्येक नियोक्ता, Annexure-A हेतु अपेक्षित उन विवरणों के संबंध में जो बिहार नियमों के अधीन विहित प्रपत्रों में समाविष्ट नहीं हैं, अर्थात् जिले का भूकंपीय क्षेत्र और बाढ़ श्रेणी, पहुँच मार्ग की चौड़ाई, कार्यस्थल की ऊँचाई, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति श्रेणी, प्रतिष्ठान का MAH प्रतिष्ठापन होने या न होने की स्थिति, तथा पाली कार्य का प्रतिरूप,

के संबंध में पोर्टल पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा; और उसमें किसी परिवर्तन के होने पर पंद्रह दिनों के भीतर घोषणा को अद्यतन करेगा।

- (4) वर्गीकरण, नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसूचित किया जाएगा और उस वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा जिसमें इसकी संगणना की गई है, जब तक कि इसे पैराग्राफ 12, पैराग्राफ 13 या पैराग्राफ 14 के अधीन परिवर्तित न किया जाए।
- (5) कोई प्रतिष्ठान जो प्रथम बार रजिस्ट्रीकृत हुआ है, जिसके संबंध में कोई अनुपालन या दुर्घटना इतिहास उपलब्ध नहीं है, तब तक मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक कि उसकी प्रथम वार्षिक विवरणी दाखिल किए जाने पर वर्गीकरण की पुनःसंगणना न कर दी जाए, जब तक कि उस पर पैराग्राफ 5 लागू न होता हो।

12. स्वतः प्रोन्नयन (Automatic Escalation)।—

- (1) संहिता की धारा 10, धारा 11 या धारा 12 के अधीन किसी प्रतिष्ठान के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, अथवा प्रपत्र—XII में प्रतिषेधया सुधार सूचना जारी किए जाने पर, उस प्रतिष्ठान की जोखिम श्रेणी पोर्टल पर स्वतः उच्च जोखिम में प्रोन्नत (escalate) हो जाएगी।
- (2) कोई प्रतिष्ठान जिसकी श्रेणी उपपैराग्राफ (1) के अधीन प्रोन्नत की गई है, ऐसे प्रोन्नयन के तीस दिनों के भीतर निरीक्षित किया जाएगा।
- (3) इस पैराग्राफ के अधीन प्रोन्नयन, संहिता की धारा 38 के अधीन निरीक्षक—सह—सुकारक की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभावी होगा।

13. स्वतः अवनयन (Automatic De-escalation)।—जहाँ किसी प्रतिष्ठान को लगातार तीन नियमित निरीक्षणों में संहिता और बिहार नियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए पाया गया है, और उस अवधि के दौरान उसके संबंध में धारा 10, 11 या 12 के अधीन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वहाँ उसका जोखिम स्कोर पोर्टल पर घटाया जाएगा और उसे अगली निम्नतर श्रेणी में रखा जाएगा परंतु पैराग्राफ 5 के अंतर्गत आने वाले किसी प्रतिष्ठान का इस पैराग्राफ के अधीन अवनयन (De-escalation) नहीं किया जाएगा।

14. प्रतिवेदन और पुनर्विलोकन।—

- (1) कोई नियोक्ता जो अपने प्रतिष्ठान के वर्गीकरण से व्यथित है, उसके संसूचन के तीस दिनों के भीतर, आधार बताते हुए और सहायक विवरण संलग्न करते हुए, मुख्य निरीक्षक—सह—सुकारक को पोर्टल पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) मुख्य निरीक्षक—सह—सुकारक, नियोक्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्रतिवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर एक तर्कसंगत आदेश द्वारा उसका निपटान करेगा, और आदेश नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसूचित किया जाएगा।
- (3) प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने मात्र से वर्गीकरण अथवा पैराग्राफ 10 या पैराग्राफ 12 के अधीन आसन्न किसी निरीक्षण पर स्वयमेव कोई स्थगन प्रभावी नहीं होगा।

15. व्यावृत्ति।—

- (1) इस योजना में कोई बात—
 - (क) किसी प्रतिष्ठान को संहिता, बिहार नियमों, अथवा उनके अधीन बनाए गए किसी विनियम, मानक या उपविधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य, बाध्यता या दायित्व से छूट नहीं देगी;
 - (ख) संहिता की धारा 35 के अधीन निरीक्षक—सह—सुकारक की किसी शक्ति को, अथवा संहिता की धारा 38 के अधीन किसी विशेष शक्ति को, निर्बंधित या न्यूनीकृत नहीं करेगी; अथवा
 - (ग) संहिता की धारा 34 के अधीन मुख्य निरीक्षक—सह—सुकारक की शक्तियों के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी।
- (2) किसी प्रतिष्ठान का मध्यम जोखिम या निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकरण, और ऐसे वर्गीकरण से प्रवाहित नियमित निरीक्षण से कोई छूट, वहाँ लागू नहीं होगी जहाँकृ
 - (क) संहिता या बिहार नियमों के अधीन किसी दुर्घटना, खतरनाक घटना या अधिसूचनीय रोग (notifiable disease) के पश्चात् विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निरीक्षण या जाँच किया जाना अपेक्षित है;

- (ख) किसी कामगार, पंजीकृत ट्रेड यूनियन अथवा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर निरीक्षण किया जाता है;
- (ग) राज्य सरकार, श्रम आयुक्त अथवा मुख्य निरीक्षक—सह—सुकारक द्वारा, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, निरीक्षण निदेशित किया जाता है; अथवा
- (घ) किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अनुसरण में निरीक्षण अपेक्षित है।
- (3) जहाँ किसी शिकायत पर निरीक्षण किया जाता है, वहाँ शिकायतकर्ता की पहचान, यदि वह ऐसा चाहता है, किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता को प्रकट नहीं की जाएगी।

16. प्रकाशन और पारदर्शिता।—

- (1) **Annexure-A** में उपवर्णित मापदण्डों, संगणना की पद्धति, और प्रतिष्ठानवार वर्गीकरण, संहिता की धारा 34 की उपधारा (4) के खंड (ख) को अग्रसर करते हुए, पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे, तथा नियोक्ताओं और कामगारों के लिए सुलभ होंगे।
- (2) इस योजना के अधीन वर्गीकृत प्रतिष्ठानों की सूची, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से अन्यथा नहीं, पोर्टल पर पुनरीक्षित और पुनःप्रकाशित की जाएगी।

17. कारखानों से भिन्न प्रतिष्ठान।—

- (1) अनुबंध—क, कारखानों के संदर्भ में अभिकल्पित किया गया है, और उसके क्रम संख्या 2, 13, 14, 15 और 16 पर स्थित प्राचल कारखानों पर लागू होते हैं।
- (2) किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में जो कारखाना नहीं है, जिसमें भवन या अन्य निर्माण कार्य, ठेका श्रम या अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाला प्रतिष्ठान, मोटर परिवहन उपक्रम, बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठान अथवा बागान सम्मिलित हैं, जो मापदण्ड लागू नहीं होते हैं, उन्हें पोर्टल पर “लागू नहीं” अभिलिखित किया जाएगा और **Annexure-A** की टिप्पणी 4 में उपबंधित रीति से संगणना से अपवर्जित किया जाएगा; और ऐसी दशा में वर्गीकरण मुख्यतः पैराग्राफ 4, 5, 6 और 8 द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (3) राज्य सरकार, संहिता की धारा 34 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन पश्चात्त्वर्ती अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए क्षेत्र—विशिष्ट मापदण्ड अधिसूचित कर सकेगी, और ऐसी अधिसूचना पर वे मापदण्ड, उपपैराग्राफ (2) के अधीन लागू नहीं होने वाले घोषित मापदण्डों के स्थान पर, लागू किए जाएंगे।

(संचिका संख्या—01/F1-105/2016—204/श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

27 अगस्त 2026

एस० ओ० 204—203 दिनांक 31 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संचिका संख्या—01/F1-105/2016—205/श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 27th August 2026

S.O. 203, dated 31st August 2026—Whereas, clause (i) of sub-section (3) of **section 34** of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) empowers the appropriate Government, by notification, to lay down an inspection scheme which may provide for the generation of web-based inspection and calling of information electronically;

And whereas, sub-section (4) of **section 34** of the said Code provides that such inspection scheme may be designed taking into account, inter alia, provisions for special inspections based on such parameters as may be notified by the appropriate Government, and the characteristics of employment, the nature of work and the characteristics of the workplaces based on such parameters as may be notified by the appropriate Government;

And whereas, sub-rule (2) of **rule 32** of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026 requires the State Government, by notification, to mandate inspection of all establishments and to lay down a web-based inspection scheme based on risk assessment of the establishment;

And whereas, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India has, under the Business Reforms Action Plan for the year 2026, advised the classification of establishments into High, Medium and Low risk categories for the purpose of risk-based inspection;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (3) read with clauses (c) and (d) of sub-section (4) of **section 34** of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and sub-rule (2) of **rule 32** of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026, the Governor of Bihar is pleased to notify the following scheme for the classification of establishments into Low Risk, Medium Risk and High Risk categories, namely:—

1. Short title, application and commencement.—

- (1) This scheme may be called the Bihar Risk-Based Classification of Establishments (Occupational Safety, Health and Working Conditions) Scheme, 2026.
- (2) It shall apply to every establishment situated in the State of Bihar to which the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 applies and in respect of which the State Government is the appropriate Government.
- (3) Nothing in this scheme shall apply to any establishment falling within the Central sphere under clause (d) of sub-section (1) of **section 2** of the Code, or to any mine, or to any establishment in respect of which the Central Government is the appropriate Government.

- (4) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

- (1) In this scheme, unless the context otherwise requires,—
- (a) **"Code"** means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020);
 - (b) **"Bihar Rules"** means the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026;
 - (c) **"calendar year"** means the period from the 1st day of January to the 31st day of December;
 - (d) **"Major Accident Hazard installation" or "MAH installation"** means an establishment in which any hazardous substance specified in **Schedule-II** to the Bihar Rules, framed under **rule 2(7)** thereof and referable to clause (zb) of sub-section (1) of **section 2** of the Code, is manufactured, processed, handled or stored in a quantity equal to or exceeding the threshold quantity specified against it in that Schedule;
 - (e) **"hazardous process"** has the meaning assigned to it in clause (za) of sub-section (1) of **section 2** of the Code read with the **First Schedule** thereto;
 - (f) **"Portal"** means the web-based inspection portal maintained by the Department under sub-rule (2) of **rule 32** of the Bihar Rules;
 - (g) **"risk score"** means the score computed in accordance with **Annexure-A** to this scheme;
 - (h) **"routine inspection"** means an inspection carried out in the ordinary course under the inspection scheme, and does not include an inspection referred to in paragraph 15;
 - (i) **"worker"** has the meaning assigned to it in clause (zzl) of sub-section (1) of **section 2** of the Code, and for the purposes of every threshold under this scheme shall include contract labour within the meaning of clause (m), and inter-State migrant workers, engaged in the establishment.
- (2) Words and expressions used and not defined in this scheme but defined in the Code or in the Bihar Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or those Rules.

3. Classification of establishments.—

- (1) Every establishment shall be classified into one of three categories, namely High Risk, Medium Risk and Low Risk.
- (2) Classification shall be made on the basis of—
 - (a) the qualitative criteria specified in paragraphs 4, 6 and 8; and
 - (b) the risk score computed under **Annexure-A**.
- (3) Where the category resulting from the criteria in paragraphs 4, 6 and 8 differs from the category resulting from the risk score under Annexure-A, the establishment shall be placed in **the higher of the two categories**.
- (4) Paragraph 5 shall have effect notwithstanding anything contained in sub-paragraph (3) or in Annexure-A.

4. High Risk establishments.—An establishment shall be classified as **High Risk** if **any one or more** of the following applies to it:—

- (a) an accident causing death, or causing bodily injury of the description notified under **section 10** of the Code, has occurred in the establishment and has been notified, or was required to be notified, during the preceding three calendar years;
- (b) a dangerous occurrence required to be notified under **section 11** of the Code, or a disease specified in the **Third Schedule** to the Code required to be notified under **section 12** thereof, has occurred during the preceding calendar year;
- (c) proceedings have been instituted during the preceding three calendar years in respect of an offence which is not compoundable under sub-section (1) of **section 114** of the Code, or under the corresponding provisions of the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020 or the Code on Social Security, 2020, or a first information report has been lodged in respect of the employment of a child;
- (d) the establishment is a factory in which five hundred workers or more are ordinarily employed, or a factory carrying on a hazardous process, or a building or other construction work, in which two hundred fifty workers or more are ordinarily employed, being the thresholds specified in sub-section (2) of **section 22** of the Code for the appointment of safety officers;
- (e) more than fifty per cent. of the workers engaged in the establishment are contract labour or inter-State migrant workers, or contract labour is engaged in any core activity of the establishment otherwise than as permitted by **section 57** of the Code;

- (f) a prohibition or improvement notice issued in **FORM-XII** under **rule 34** of the Bihar Rules is outstanding and has not been complied with within the period specified therein;
- (g) the risk score computed under Annexure-A is 4.5 or above; or
- (h) the establishment falls within paragraph 5.

5. Establishments mandatorily classified as High Risk.—Notwithstanding the risk score computed under Annexure-A, an establishment shall in every case be classified as **High Risk**, and shall not be eligible for classification as Medium Risk or Low Risk, if it—

- (a) is an MAH installation;
- (b) carries on any hazardous process within the meaning of clause (za) of sub-section (1) of **section 2** of the Code read with the **First Schedule** thereto; or
- (c) manufactures, processes, handles or stores any hazardous substance specified in **Schedule-II** to the Bihar Rules in a quantity equal to or exceeding the threshold quantity specified therein.

6. Medium Risk establishments.—

- (1) An establishment which is not classified as High Risk under paragraph 4 or paragraph 5, and which does not satisfy every condition specified in paragraph 8, shall be classified as **Medium Risk**.
- (2) Without prejudice to sub-paragraph (1), an establishment shall be classified as Medium Risk where the only proceedings instituted against it during the preceding three calendar years relate to an offence which is compoundable under sub-section (1) of **section 114** of the Code, or which is liable to a penalty imposable after inquiry by an authority notified by the Department.
- (3) An establishment whose risk score computed under Annexure-A is 2.5 or above but below 4.5 shall be classified as Medium Risk, subject to paragraphs 4 and 5.

7. Third party audit and certification for Medium Risk establishments.—

- (1) Medium Risk establishments are hereby specified as a **class of establishments** for the purposes of sub-section (1) of **section 37** of the Code.
- (2) The State Government shall, by a separate notification under sub-section (1) of **section 37** of the Code read with **rule 35** of the Bihar Rules,

- formulate a scheme to empanel experts and shall notify the specialised qualification and experience, duties and responsibilities of such experts.
- (3) Nothing in sub-paragraphs (4) to (7) shall have effect until the notification referred to in sub-paragraph (2) has been published in the Official Gazette.
 - (4) The third party audit and certification of a Medium Risk establishment shall be **assigned by the Department to an empanelled expert in a randomised manner through the Portal**, in accordance with clause (a) of sub-section (2) of **section 37** of the Code; and no establishment shall itself select, appoint or engage the expert who audits it.
 - (5) The empanelled expert shall carry out both the audit **and** the certification in the manner specified in the scheme, and shall submit the report **to the employer and to the Inspector-cum-Facilitator** having jurisdiction, in accordance with clause (c) of sub-section (2) of **section 37** of the Code.
 - (6) Where a Medium Risk establishment has been so audited and certified, and the audit report has been submitted within the time specified in the scheme, the establishment shall be exempt from routine inspection for the period specified in the scheme.
 - (7) The exemption under sub-paragraph (6) shall not be available, and the establishment shall be taken up for routine inspection, where the establishment—
 - (a) fails to make itself available for the audit assigned to it, or fails to file the audit report, within the time specified; or
 - (b) fails to furnish the annual return in **FORM-IX** within the time specified in **rule 29** of the Bihar Rules.

8. Low Risk establishments.—

An establishment shall be classified as **Low Risk** only if **all** of the following conditions are satisfied:—

- (a) it is not an establishment falling within paragraph 4 or paragraph 5;
- (b) no accident, dangerous occurrence or notifiable disease required to be reported under **sections 10, 11 or 12** of the Code has occurred in the establishment during the preceding five calendar years;
- (c) no prosecution has been instituted against the establishment under any of the labour codes during the preceding five calendar years;
- (d) the annual return in **FORM-IX** has been duly furnished for each of the preceding three calendar years within the time specified in **rule 29** of the Bihar Rules; and

- (e) the risk score computed under Annexure-A is below 2.5.

9. Self-certification for Low Risk establishments.—

- (1) A Low Risk establishment shall be entitled to the facility of self-certification in respect of the compliances arising under the Code and the Bihar Rules, subject to the following conditions:—
 - (a) the establishment is included in the self-certification scheme notified by the State Government;
 - (b) the establishment uploads its annual return in **FORM-IX** on the Portal within the time specified in **rule 29** of the Bihar Rules and maintains the prescribed registers and records in electronic form; and
 - (c) the establishment uploads the self-certificate in the form prescribed by the State Government on the Portal for each year.
- (2) An establishment which fails to upload the annual return within the time so specified shall not be entitled to the benefit of self-certification or to the reduced inspection frequency under paragraph 10, and shall be treated as a Medium Risk establishment for that year.
- (3) The Department shall each year cause not less than five per cent. of the self-certified Low Risk establishments, selected at random through the Portal, to be verified by inspection.
- (4) Where a self-certificate is found to be false in any material particular, the establishment shall be reclassified as High Risk with effect from the date of such finding, the facility of self-certification shall stand withdrawn for three years, and action shall be taken under the relevant penal provisions of the Code.

10. Frequency of routine inspection.—

- (1) Routine inspections shall be assigned through the Portal by randomised selection of the establishment and of the Inspector-cum-Facilitator, in accordance with clause (ii) of sub-section (3) of **section 34** of the Code.
- (2) Subject to paragraph 15, the frequency of routine inspection shall ordinarily be—
 - (a) **High Risk** — at least once in every calendar year;
 - (b) **Medium Risk** — at least once in every three calendar years, or as provided in sub-paragraph (6) of paragraph 7 where the establishment has been audited and certified under that paragraph; and
 - (c) **Low Risk** — at least once in every five calendar years.

- (3) In order to give effect to clause (c) of sub-paragraph (2) and to the requirement in sub-rule (2) of **rule 32** of the Bihar Rules that inspection of all establishments be mandated, the Portal shall in each year select for inspection **approximately one-fifth** of the Low Risk establishments, so that every Low Risk establishment is inspected at least once in every five calendar years; and the number so selected in any year shall not exceed twenty per cent. of the total number of Low Risk establishments.

11. Computation, communication and validity of classification.—

- (1) The risk score and the resulting classification shall be computed on the Portal—
 - (a) at the time of registration of the establishment under **section 3** of the Code or, in the case of a factory, at the time of grant or renewal of the licence under **rule 64** of the Bihar Rules; and
 - (b) afresh in each year, upon the filing of the annual return in **FORM-IX**.
- (2) The classification shall be computed from the particulars available in the application for registration, the licence, the annual return, the registers maintained under **section 33** of the Code, the register of accidents and dangerous occurrences in **FORM-X** under **rule 30** of the Bihar Rules, and the self-declaration furnished under sub-paragraph (3).
- (3) Every employer shall furnish on the Portal a self-declaration in respect of those particulars required for Annexure-A which are not captured in the forms prescribed under the Bihar Rules, namely the seismic zone and flood category of the district, the width of the approach road, the elevation of the workplace, the consent category assigned by the Bihar State Pollution Control Board, the status of the establishment as an MAH installation or otherwise, and the pattern of shift working; and shall update the declaration within fifteen days of any change therein.
- (4) The classification shall be communicated to the employer electronically and shall be valid for the financial year in which it is computed, unless altered under paragraph 12, paragraph 13 or paragraph 14.
- (5) An establishment registered for the first time, in respect of which no compliance or accident history is available, shall be classified as **Medium Risk** until the classification is recomputed upon the filing of its first annual return, unless paragraph 5 applies to it.

12. Automatic escalation.—

- (1) On receipt of a notice under **section 10**, **section 11** or **section 12** of the Code in respect of any establishment, or on the issue of a prohibition or improvement notice in **FORM-XII**, the risk category of that establishment shall stand automatically escalated to **High Risk** on the Portal.
- (2) An establishment whose category has been escalated under sub-paragraph (1) shall be inspected within thirty days of such escalation.
- (3) Escalation under this paragraph shall take effect without prejudice to the powers of the Inspector-cum-Facilitator under **section 38** of the Code.

13. Automatic de-escalation.—

Where an establishment has been found, on three consecutive routine inspections, to be in compliance with the provisions of the Code and the Bihar Rules, and no notice under **sections 10**, **11** or **12** has been received in respect of it during that period, its risk score shall be reduced on the Portal and it shall be placed in the next lower category: provided that no establishment falling within paragraph 5 shall be de-escalated under this paragraph.

14. Representation and review.—

- (1) An employer aggrieved by the classification of his establishment may, within thirty days of its communication, make a representation on the Portal to the **Chief Inspector-cum-Facilitator**, stating the grounds and enclosing the supporting particulars.
- (2) The Chief Inspector-cum-Facilitator shall, after giving the employer an opportunity of being heard, dispose of the representation by a speaking order within sixty days of its receipt, and the order shall be communicated electronically to the employer.
- (3) The making of a representation shall not by itself operate to stay the classification or any inspection due under paragraph 10 or paragraph 12.

15. Savings.—

- (1) Nothing in this scheme shall—
 - (a) exempt any establishment from any duty, obligation or liability imposed upon it by the Code, the Bihar Rules, or any regulation, standard or bye-law made thereunder;
 - (b) restrict or abridge any power of an Inspector-cum-Facilitator under **section 35** of the Code, or any special power under **section 38** of the Code; or

- (c) affect the exercise of the powers of the Chief Inspector-cum-Facilitator under **section 34** of the Code.
- (2) The classification of an establishment as Medium Risk or Low Risk, and any exemption from routine inspection flowing from such classification, shall **not** apply where—
 - (a) an inspection or inquiry is required to be made within a specified period following an accident, dangerous occurrence or notifiable disease under the Code or the Bihar Rules;
 - (b) an inspection is undertaken on a complaint received from a worker, a registered trade union or any other person;
 - (c) an inspection is directed by the State Government, the Labour Commissioner or the Chief Inspector-cum-Facilitator for reasons to be recorded in writing; or
 - (d) an inspection is required in pursuance of an order of any court or tribunal.
- (3) Where an inspection is undertaken on a complaint, the identity of the complainant shall not be disclosed to the employer in any circumstance if the complainant so desires.

16. Publication and transparency.—

- (1) The parameters set out in Annexure-A, the method of computation, and the establishment-wise classification shall be published on the Portal, and shall be accessible to employers and to workers, in furtherance of clause (b) of sub-section (4) of **section 34** of the Code.
- (2) The list of establishments classified under this scheme shall be revised and republished on the Portal in each year, not later than 31st March.

17. Establishments other than factories.—

- (1) Annexure-A has been designed with reference to factories, and the parameters at serial numbers 2, 13, 14, 15 and 16 thereof are applicable to factories.
- (2) In relation to an establishment which is not a factory, including a building or other construction work, an establishment engaging contract labour or inter-State migrant workers, a motor transport undertaking, a beedi and cigar establishment or a plantation, the parameters which are not applicable shall be recorded on the Portal as "Not applicable" and shall be excluded from the computation in the manner provided in Note 4 to

Annexure-A; and the classification shall in such case be determined principally by paragraphs 4, 5, 6 and 8.

- (3) The State Government may, by a subsequent notification under clause (d) of sub-section (4) of **section 34** of the Code, notify sector-specific parameters for such establishments, and upon such notification those parameters shall be applied in place of the parameters declared inapplicable under sub-paragraph (2).

(No. 01/F1-105/2016-204/L.R.)
By order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to Government.

ANNEXURE-A

[See paragraphs 3, 4(g), 6(3), 8(e) and 11]

PARAMETERS AND SCORES FOR COMPUTATION OF THE RISK SCORE

Sl. No.	Parameter	Statutory basis / source of data	Score
PART I — SCALE AND SITING OF THE ESTABLISHMENT			
1	Number of workers ordinarily employed on any day (i) fewer than 20 (ii) 20 or more but fewer than 50 (iii) 50 or more but fewer than 100 (iv) 100 or more but fewer than 250 (v) 250 or more	"Worker" as defined in section 2(1)(zzl) of the Code, including contract labour under section 2(1)(m) and inter-State migrant workers. Source: application for registration under section 3 ; licence under rule 64 ; annual return in FORM-IX .	02 04 06 09 10
2	Total rated capacity of machinery and plant installed, expressed in horse power (i) up to 50 H.P. (ii) above 50 H.P. but below 500 H.P. (iii) 500 H.P. or above	Computed in the manner set out in the Note to Schedule-III (Fee) to the Bihar Rules. Source: factory licence under rule 64 and amendment thereof under rule 64(7) . Applicable to factories only.	02 06 08
3	Location of the establishment (i) within 1 km. of a municipal area (ii) within a municipal area (iii) within a municipal area and adjoining a public place (hospital, railway station, school, market, place of worship) (iv) elsewhere	Self-declaration under paragraph 11(3), verified against the registered address of the establishment.	03 04 06 02
4	Seismic zone of the district in which the establishment is situated (see Table 1 below) (i) Zone III (Moderate) (ii) Zone IV (High) (iii) Zone V (Highest)	IS 1893 (Part 1) seismic zoning map of India. No district of Bihar falls in Zone II.	03 04 05
5	Flood vulnerability of the district (see Table 2 below) (i) Vulnerable district (ii) Most vulnerable district (iii) Other district	Flood-prone district classification of the Water Resources Department, Government of Bihar.	04 05 Nil
6	Proximity to an MAH installation (i) within 500 metres of an MAH installation (ii) otherwise	Distance of 500 metres adopted from Sub-Schedule-2 of Schedule-II to the Bihar Rules (isolated storage installations).	05 Nil

Sl. No.	Parameter	Statutory basis / source of data	Score
PART II — NATURE OF THE PROCESS AND SUBSTANCES HANDLED			
7	Establishment is an MAH installation (i) yes (ii) no	Hazardous substances and threshold quantities specified in Schedule-II to the Bihar Rules, made under rule 2(7) thereof and referable to section 2(1)(zb) of the Code. Note: see paragraph 5 — mandatory High Risk.	10 Nil
8	Establishment carries on a hazardous process (i) yes (ii) no	Section 2(1)(za) of the Code read with the First Schedule to the Code (list of industries involving hazardous processes). Note: see paragraph 5 — mandatory High Risk.	08 Nil
9	Establishment carries on any dangerous operation or special process (i) yes (ii) no	Sub-Schedules 1 to 25 of Schedule-IV to the Bihar Rules; and any establishment notified under rule 38 of the Bihar Rules as engaged in a dangerous occupation or process.	07 Nil
10	Storage of hazardous chemicals (i) below the threshold quantity (ii) at or above the threshold quantity (iii) no hazardous chemical stored	Schedule-II to the Bihar Rules (Sub-Schedule-1: list of hazardous chemicals; Sub-Schedule-2: isolated storage; Sub-Schedule-3: threshold quantities).	07 09 Nil
11	Consent category of the establishment (i) White / non-polluting (ii) Green (iii) Orange (iv) Red	Category assigned by the Bihar State Pollution Control Board in the consent to operate, applying the classification of the Central Pollution Control Board.	02 04 06 08
12	Exposure of workers to any occupational health hazard capable of causing a notifiable disease (i) yes (ii) no	Third Schedule to the Code (list of notifiable diseases), referable to section 12(1) of the Code.	06 Nil
PART III — CHARACTERISTICS OF THE WORKPLACE			
13	Working in shifts (i) general shift only (ii) two or more shifts (iii) continuous or night-shift working	Notice of periods of work displayed under section 33 of the Code and rule 28 of the Bihar Rules.	Nil 04 05
14	Width of the approach road serving the establishment (i) less than 20 feet (6 metres) (ii) 20 feet (6 metres) or more	Self-declaration under paragraph 11(3). Relevant to emergency and fire-tender access.	06 Nil

Sl. No.	Parameter	Statutory basis / source of data	Score
15	Elevation of the workplace (i) ground floor only (ii) on or above the first floor, or in a basement (iii) on or above the fourth floor, or above 40 feet from ground level	Self-declaration under paragraph 11(3), read with the building plan approved at the time of grant of licence.	Nil 04 06
16	Fire load density of the workplace (i) low (up to 275 MJ/sq.m.) (ii) moderate (above 275 and up to 550 MJ/sq.m.) (iii) high (above 550 MJ/sq.m.)	Fire load density as certified in the fire safety certificate issued by the competent authority, applying the classification in the National Building Code of India, 2016. Note: the classification of fire-prone factories into Classes A to E under the Bihar Factories Rules, 1950 is not available, those Rules having been superseded by the Bihar Rules.	03 05 08
PART IV — SAFETY AND COMPLIANCE PERFORMANCE			
17	Accidents notified during the preceding three calendar years (i) none (ii) one or more accidents causing reportable bodily injury (iii) one or more accidents causing death	Section 10 of the Code; register of accidents in FORM-X under rule 30 of the Bihar Rules.	Nil 07 10
18	Dangerous occurrences notified during the preceding three calendar years (i) none (ii) one or more	Section 11 of the Code; register in FORM-X under rule 30 of the Bihar Rules.	Nil 07
19	Notifiable diseases reported during the preceding three calendar years (i) none (ii) one or more	Section 12 of the Code read with the Third Schedule thereto.	Nil 08
20	Prosecutions instituted during the preceding three calendar years (i) none (ii) for a compoundable offence only (iii) for an offence not compoundable under section 114(1) , or a first information report for employment of a child	Section 114 of the Code; prosecution records of the Department.	Nil 05 10
21	Prohibition or improvement notices outstanding (i) none (ii) one or more not complied with within the period specified	FORM-XII issued under rule 34 of the Bihar Rules.	Nil 09

NOTES ON COMPUTATION

Note 1. The Annexure contains twenty-one parameters. Every parameter shall be assigned exactly one score from column 4.

Note 2. The score scale runs from 0 to 10. A higher score denotes a higher level of risk.

Note 3. Where the entry against a parameter is "Nil", that parameter shall be assigned a score of zero and shall be **counted** in the value of "n" in Note 5.

Note 4. Where a parameter is **not applicable** to the establishment by reason of paragraph 17 of this scheme, the Portal shall record it as "Not applicable" and it shall be **excluded** from the value of "n" in Note 5. A parameter shall not be recorded as "Not applicable" merely because the establishment scores nil against it.

Note 5. The **risk score** is the root mean square of the individual scores assigned under this Annexure, that is to say, where a, b, c ... n are the individual scores assigned and "n" is the number of parameters so scored (excluding parameters recorded as "Not applicable"), the risk score is—

$$\text{Risk score} = \{ (a^2 + b^2 + c^2 + \dots + n^2) / n \}^{1/2}$$

Note 6. The risk score shall be computed on the Portal and expressed to two decimal places.

Note 7. The categories corresponding to the risk score are—

- (a) risk score 4.50 or above — **High Risk**;
- (b) risk score 2.50 or above but below 4.50 — **Medium Risk**;
- (c) risk score below 2.50 — **Low Risk**.

Note 8. The categories in Note 7 are subject to paragraph 5 of this scheme, under which an MAH installation, an establishment carrying on a hazardous process, and an establishment storing hazardous chemicals at or above the threshold quantity shall in every case be classified as High Risk irrespective of the risk score; and are subject to paragraph 3(3), under which the higher of the two categories prevails.

TABLE 1 — SEISMIC ZONE OF DISTRICTS OF BIHAR

[See serial number 4 of this Annexure.] Each of the thirty-eight districts of the State appears in **one zone only**. Where a district has been reorganised, the zone of the successor district shall be that of the predecessor district until otherwise notified.

Zone	Districts	No. of districts	Score
Zone II (Least active)	Nil — no district of Bihar falls in Zone II.	0	Not applicable
Zone III (Moderate)	Bhojpur (Ara), Buxar, Rohtas, Kaimur, Aurangabad, Gaya, Nawada, Jehanabad, Arwal.	9	03
Zone IV (High)	West Champaran (Bettiah), East Champaran (Motihari), Gopalganj, Siwan, Saran, Vaishali, Samastipur, Patna, Nalanda, Sheikhpura, Lakhisarai, Begusarai, Khagaria, Munger, Jamui, Banka, Bhagalpur, Katihar.	18	04

Zone	Districts	No. of districts	Score
Zone V (Highest)	Sitamarhi, Sheohar, Muzaffarpur, Darbhanga, Madhubani, Supaul, Saharsa, Madhepura, Araria, Kishanganj, Purnia.	11	05
Total		38	

TABLE 2 — FLOOD VULNERABILITY OF DISTRICTS OF BIHAR

[See serial number 5 of this Annexure.] Each of the thirty-eight districts of the State appears in one category only.

Category	Districts	No. of districts	Score
Vulnerable	West Champaran, Gopalganj, Siwan, Saran, Buxar, Bhojpur, Patna, Nalanda, Lakhisarai, Sheikhpura, Purnia, Araria, Kishanganj.	13	04
Most vulnerable	East Champaran, Sheohar, Sitamarhi, Madhubani, Darbhanga, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur, Supaul, Saharsa, Madhepura, Khagaria, Begusarai, Bhagalpur, Katihar.	15	05
Other districts	Rohtas, Kaimur, Aurangabad, Gaya, Nawada, Jehanabad, Arwal, Munger, Jamui, Banka.	10	Nil
Total		38	

By order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1060-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>